

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 122]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 23 मार्च 2017—चैत्र 2, शक 1939

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 23 मार्च 2017

क्र. 8077-वि.स.-विधान-2017.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 64 के उपबंधों के पालन में, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 9 सन् 2017) जो विधान सभा में दिनांक 23 मार्च 2017 को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

अवधेश प्रताप सिंह  
प्रमुख सचिव,  
मध्यप्रदेश विधान सभा.

**मध्यप्रदेश विधेयक**

क्रमांक ९ सन् २०१७

**मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक, २०१७**

विषय-सूची.

खण्ड :

१. संक्षिप्त नाम.
२. धारा १ का संशोधन.
३. धारा २ का संशोधन.
४. धारा १६ का संशोधन.
५. धारा २३-क का संशोधन.
६. धारा २३-ग और २३-घ का अंतःस्थापन.
७. धारा ३४ का लोप.

**मध्यप्रदेश विधेयक**

क्रमांक ९ सन् २०१७

**मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक, २०१७**

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, १९७३ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) अधिनियम, २०१७ है.

धारा १ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, १९७३ (क्रमांक २३ सन् १९७३) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा १ में, उपधारा (४) में,—

(एक) खण्ड (ख) में, सेमी-कोलन के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और उसके पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“परन्तु रक्षा संकर्म अधिनियम, १९०३ ( १९०३ का ३) के उपबंध के अधीन प्रतिबंधित क्षेत्र के रूप में घोषित और अधिसूचित क्षेत्र में निवेश अनुज्ञाप प्राप्त करने के लिए कमान अधिकारी से पूर्विक अनापत्ति प्रमाण-पत्र अपेक्षित है;”;

(दो) खण्ड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“(ग) रेल अधिनियम, १९८९ ( १९८९ का २४) के अधीन, रेल प्रशासन के नियंत्रणाधीन भूमियों को,”.

धारा २ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा २ में,—

(एक) खण्ड (छ) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किए जाएं, अर्थात् :—

“(छ क) “विकास अधिकार प्रमाण-पत्र (डी आर सी)” से अभिप्रेत है, इसके धारक को स्थानांतरणीय विकास अधिकार प्रदान करने वाला और राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन हेतु प्राधिकृत किसी प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र ;

(छ ख) “विकास अधिकार प्रमाण-पत्र लेखा” से अभिप्रेत है, प्राधिकारी द्वारा संधारित एक सारणीकृत लेखा जिसमें उत्पादन क्षेत्र, कुल आवंटित क्षेत्र, किसी भी समय स्थानांतरित क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र को खरीदने वाले व्यक्ति और प्राप्त क्षेत्र की प्रविष्टियां हों;”;

(दो) खण्ड (झ) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“(झ क) “उत्पादन-क्षेत्र” से अभिप्रेत है, किसी लोक परियोजना के लिए प्रस्तावित क्षेत्र जिसमें सम्मिलित हैं सरकार और उसके उपक्रमों द्वारा संबंधित योजना क्षेत्र में लोक प्रसुविधाएं तथा सुविधाएं, आमोद-प्रमोद, परिवहन, गंदी बस्ती पुनर्वासन, लोक गृह निर्माण तथा कोई अन्य विशेष उपयोग, जो ऐसे प्ररूप में, जैसा कि विहित किया जाए अधिसूचित किया जाएगा;”;

(तीन) खण्ड (ण ण) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“(ण ण क) “प्राप्ति क्षेत्र” से अभिप्रेत है, संचालक द्वारा अधिसूचित ऐसा क्षेत्र जहां कोई व्यक्ति आधार फर्श क्षेत्र अनुपात की अपेक्षा अधिक फर्श क्षेत्र निर्माण हेतु अर्जित अधिकार का उपयोग करने के लिए अनुज्ञात है;”;

(चार) खण्ड (फ) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“(फ क) “विकास अधिकारों का अंतरण (टी डी आर)” से अभिप्रेत है, भूमि के स्वामी द्वारा अभ्यर्पित अथवा त्यजित क्षेत्र के बदले अतिरिक्त निर्मित क्षेत्र की निश्चित मात्रा उपलब्ध कराना, ताकि वह अधिक निर्मित-क्षेत्र का या तो स्वयं उपयोग कर सके अथवा उसे अतिरिक्त निर्मित क्षेत्र की आवश्यकता वाले किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरित कर सके;”;

४. मूल अधिनियम की धारा १६ में, उपधारा (५) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

धारा १६ का संशोधन.

“(५) धारा २९ की उपधारा (३), धारा ३१, धारा ३२ तथा धारा ३३ के अधीन क्रमशः उपांतरण, अपील, पुनरीक्षण तथा अनुज्ञा के व्यपगत होने के उपबंध, जो कि धारा ३० के अधीन अनुज्ञा प्रदान करने या उससे इंकार करने वाले किसी आदेश को लागू होते हों, उपधारा (१) के अधीन किए गए किसी आदेश पर यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे.”.

५. मूल अधिनियम की धारा २३-क में,—

धारा २३-क का संशोधन.

(एक) उपधारा (१) में,—

(क) खण्ड (क) में, शब्द “नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकरण” के पश्चात् शब्द “अथवा संचालक” अंतःस्थापित किए जाएं ;

(ख) खण्ड (ख) में, शब्द “किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के संगम के दिए गए किसी ऐसे आवेदन पर” के स्थान पर, शब्द “किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के संगम द्वारा संचालक को किए गए किसी ऐसे आवेदन पर” स्थापित किए जाएं;

(दो) उपधारा (२) में,—

(क) प्रथम स्थान पर आए शब्द “राज्य सरकार” के स्थान पर, शब्द “संचालक” स्थापित किया जाए;

(ख) शब्द “और उससे प्रभावित समस्त व्यक्तियों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, राज्य सरकार, योजना को इस प्रकार उपांतरित कर सकेगी जिस प्रकार कि वह

समुचित समझे" के स्थान पर, शब्द "और उससे प्रभावित समस्त व्यक्तियों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, संचालक, प्रस्तावित उपांतरण से संबंधित समस्त दस्तावेज अपने मत के साथ राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा और, राज्य सरकार योजना को इस प्रकार उपांतरित कर सकेगी जैसी कि वह समुचित समझे" स्थापित किए जाएं.

धारा २३-ग और  
२३-घ का अंतः-  
स्थापन.

६. मूल अधिनियम की धारा २३-ख के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात् :-

विकास अधिकार  
प्रमाण-पत्र के रूप  
में अतिरिक्त निर्माण  
योग्य फर्श स्थान.

"२३-ग. जहां कोई भूमि उत्पादन क्षेत्र का भाग है, वहां सरकार या उसका उपक्रम जो कि किसी लोक परियोजना का क्रियान्वयन अभिकरण है, भूमि स्वामी को विकास अधिकार प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए प्राधिकारी को आवेदन कर सकेगा.

परियोजना क्षेत्र में  
अतिरिक्त निर्माण  
योग्य फर्श स्थान.

२३-घ. जहां कोई भूमि, शासन द्वारा अधिसूचित किसी परियोजना प्रभावित क्षेत्र का भाग है, वहां अधिकतम अनुज्ञेय अतिरिक्त निर्माणयोग्य क्षेत्र का प्रथम पचास प्रतिशत केवल परियोजना प्राधिकरण से क्रय किया जा सकता है और शेष अतिरिक्त निर्माणयोग्य क्षेत्र, विकास अधिकार प्रमाण-पत्र के माध्यम से क्रय किया जा सकेगा."

धारा ३४ का लोप.

७. मूल अधिनियम की धारा ३४ का लोप किया जाए.

## उद्देश्यों और कारणों का कथन

प्रदेश के नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र के नियोजित विकास को क्रियान्वित करने की दृष्टि से मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, १९७३ में प्रावधान है. गत वर्षों में नगरीकरण तथा विकास की नीतियों एवं प्रक्रिया में परिवर्तन हुये हैं. नगरीय क्षेत्रों में भूमि के मूल्यों में हुई वृद्धि के कारण प्रत्येक भूस्वामी द्वारा भूमि के उपयोग एवं उससे प्राप्त होने वाले लाभ प्राप्त करने की मांग भी बढ़ रही है. विकास योजना में अनेक ऐसे भूमि उपयोग समाहित रहते हैं जिनसे भूमि स्वामी को कोई वित्तीय लाभ नहीं होता, जैसे आमोद-प्रमोद एवं यातायात, किन्तु ये भू उपयोग नगर तथा समस्त जनसंख्या के लिये अत्यन्त आवश्यक होते हैं. ऐसी भूमि का भूस्वामी, उस भूमि पर लाभप्रद गतिविधि नहीं कर पाता है. उपरोक्त समस्या को दूर करने की दृष्टि से हस्तांतरणीय विकास प्राधिकार के प्रावधान अधिनियम में प्रस्तावित किये जा रहे हैं. इन प्रावधानों के द्वारा परियोजना क्षेत्र के भूस्वामी को परियोजना के क्रियान्वयन के समय, उक्त भूमि परियोजना क्रियान्वयन के समय, उक्त भूमि परियोजना क्रियान्वयन एजेन्सी में वेष्टित होने पर, हस्तांतरणीय विकास प्राधिकार (टी. डी. आर.) प्रदान किया जा सकेगा. इन प्रावधानों के लिये अधिनियम की धारा-२ में परिभाषाएं तथा धारा २३(ग) एवं २३(घ) प्रस्तावित किये जा रहे हैं. हस्तांतरणीय विकास प्राधिकार के प्रावधानों के फलस्वरूप विद्यमान धारा ३४ को विलोपित किया जा रहा है. रेल्वे एक्ट, १९८९ तथा वर्क्स ऑफ डिफेंस एक्ट, १९०३ में हुये प्रावधानों के परिपेक्ष्य में मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम के प्रावधानों को सुसंगत बनाने की दृष्टि से अधिनियम की धारा-१ में संशोधन प्रस्तावित किये जा रहे हैं. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, १९७३ में दिनांक ३-१-२०१२ को किये गये संशोधन में अधिनियम की धारा ३० में दी गई विकास अनुज्ञा को संशोधित करने के प्रावधान सम्मिलित किये गये. किन्तु इस संशोधन में धारा १६ के अंतर्गत दी गई विकास अनुज्ञा का समावेश न होने के कारण धारा १६ में दी गई विकास अनुज्ञा संशोधित नहीं की जा सकती है. धारा १६ के प्रकरणों में प्रदान की गई अनुज्ञा के संबंध में अग्रेतर कार्यवाहियां धारा ३० के अंतर्गत दी गई विकास अनुज्ञा के अनुरूप होने के कारण विकास अनुज्ञा में संशोधन के प्रावधान धारा १६ के अंतर्गत दी गई अनुज्ञा के लिये भी प्रस्तावित किये जा रहे हैं.

२. अतः विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :

दिनांक २२ मार्च, २०१७

माया सिंह

भारसाधक सदस्य.